newsjankalyanseva@gmail.com

साप्ताहिक

जनकल्याण सेवा

ठाणे | वर्ष - २२ | अंक - ४५ | २७ नवंबर से ३ दिसंबर २०२३ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

सरकारी जमीन पर बना अवैध होटेल, स्थानिय रहिवासियों में आक्रोश

विधायक प्रताप सरनाईक के बेटा ने किया अवैध होटेल का निर्माण शराब बेचने के लिए लाइसेंस का किया आवेदन

जेकेएस संवाददाता

मीरा-भाईंदर : एक सरकारी जमीन पर अवैध होटेल बनकर तैयार हो गया है। अब इस होटेल पर शराब बेचने की तैयारी चल रही है। हालांकि, मीरा भाईंदर की जिस इमारत के बाहर यह होटेल बना है, वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह जमीन विधायक प्रताप सरनाईक ने सरकार से मांगी थी कि यहां सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस जमीन को अतिक्रमण से बचाएंगे। उक्त जमीन पर अवैध निर्माण की बात को तलाठी भी स्वीकार कर तहसीलदार को कार्रवाई के लिए सूचित कर चुका है। इसके अलावा, मनपा प्रशासन को भी इस बारे में दर्जनों शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन आरोप है कि मनपा और जिला प्रशासन ने लालफीताशाही की आड़ में अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मामला तुंगा अस्पताल से सटे गौरव गार्डन के सामने की सरकारी जमीन (नवीन सर्वे- ८१) का है। एक तरफ मनपा का काम अवैध निर्माण रोकना है, तो वहीं यहां पर मनपा ने इस सरकारी जमीन पर 'शेड लगाने' के नाम पर 'अवैध निर्माण'

की 'वैध' इजाजत दी है। इस जमीन पर लाखों रुपये खर्च कर एक शानदार शेड तैयार हो चुका है। शेड जिस होटेल/दुकान/संपत्ति से सटा है, वह शिवसेना विधायक सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक का है। पूर्वेश ने इस होटेल/दुकान/संपत्ति पर शराब बेचने के लिए एफ-एल-०३ लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है। इमारत के रहिवासियों का इस अवैध शेड और शराब के लाइसेंस के लिए खुला विरोध है। खुलेआम हो रहे अवैध निर्माण पर विधायक सरनाईक ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनके बेटे ने होटेल/दुकान/संपत्ति को किराए पर दे रखा है, इसलिए उनका उससे कोई संबंध नहीं है। आज जहां सरनाईक इस अवैध निर्माण पर मौन हैं, वहीं २०१२ में उन्होंने राज्य सरकार ने इस जमीन की मांग की थी, ताकि उस पर कोई अतिक्रमण न हो। लोगों का कहना है कि जिस जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए लिया गया था, उस जमीन पर खुद सरनाईक ने ही अतिक्रमण कर लिया है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धेश राणे का कहना है कि मनपा और जिला प्रशासन पूरी तरह से सत्ताधारी विधायक के दबाव में काम कर रहा है। सत्ता के दबाव में प्रशासन खुलेआम एक सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने दे रहा है। इस बारे में मनपा आयुक्त से संपर्क नहीं हो सका।

अवैध कार्यालयों पर गिरेगी मनपा की गाज, राजनीतिक पार्टीयों में मचा हड़कंप

जेकेएस संवाददाता

मीरा-भाईंदर मनपा (एमबीएमसी) शहर में राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालयों को तोडऩे की तैयारी कर रही है। मनपा अतिक्रमण विभाग विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे कार्यालयों की सूची बना रहा है, जो अवैध है अथवा अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष २०१९ में भी तोडक कार्रवाई के लिए अवैध राजनीतिक कार्यालयों की सूची बनाई गई थी, लेकिन राजनेताओं के दवाव में मनपा ने उक्त सूची को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उम्मीद है कि इस बार वन रही सूची पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल ही में शिवसेना (शिंदे) ने शहर में जगह-जगह अवैध कंटेनर शाखाएं खोल ली थी। इनका विरोध भाजपा, शिवसेना (उद्धव), कांग्रेस और मनसे द्वारा किया गया। इसके वाद शिवसेना (शिंदे) ने भी अन्य राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालयों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद से मनपा नए सिरे से राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालयों की सूची वना रहा है। इस तरह की सूची को कंटेनर शाखा के विरोध से जोडक़र देखा जा रहा है। उम्मीद है कि आगामी एक-दो

दिन में सूचे वनकर तैयार हो जाएगी। महासभा में पारित हुआ था प्रस्ताव गौरतलब है कि शहर में राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालयों को तोडऩे के संबंध में २०१९ में महासभा में प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ था। लेकिन राजनीतिक सेटलमेंट और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर कभी अमल ही नहीं किया गया। तव जो सूची बनाई गई थी, उसमें सबसे ज्यादा १६ अवैध कार्यालय शिवसेना के ही थे। उस समय शिंदे और उद्धव की शिवसेना अलग-अलग नहीं हुई थी। चूंकि यह सारा मसला एक वार फिर शिंदे शिवसेना के अवैध कंटेनर शाखा विवाद से उठ खडा हुआ तो तो प्रश्न यह भी उठता है कि जो सूची इस वार वन रही है, क्या उसपर मनपा कार्रवाई करेगी। गौरतलब यह भी है कि शिंदे शिवसेना ने अवैध कार्यालयों पर कार्रवाई की मांग की है और पुरानी सूची के मुताविक शिवसेना के वंट जाने के वाद भी शिंदे शिवसेना के कई कार्यालय इस सूची में शामिल होंगे। ऐसे में क्या मनपा मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर इन पर कार्रवाई करेगी। पूर्व नगरसेवक रोहित सुवर्णा कहते हैं कि जिन नेताओं का काम शहर में अवैध निर्माण को रोकना था, उन्होंने ही पूरे शहर में अवैध निर्माण कर रखा है। सुवर्णा कहते हैं कि उन्हें मनपा आयुक्त संजय काटकर से उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दवाव झेलना होगा।

पूनम सागर कॉम्पलेक्स में पुलिस गस्त बढाने की मांग

मीरा रोड : मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने नया नगर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी हाशिया के नेतृत्व में भगवंती, वसीम और प्रकाश पोमान आदि पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने नया नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे से मुलाकात कर इस आशय का निवेदन सौंपा है. कॉम्प्लेक्स के रहिवासियों में दहशत का माहौल बता दें कि मीरा रोड पूर्व में ७ मंजिला ५७ बिल्डिंगों के एक बडे. समूह में पूनम सागर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से ४१ बिल्डिंगें फेडरेशन की सदस्य हैं. इस कॉम्प्लेक्स के परिसर में ड्रग्स एडिक्ट युवकों का आए दिन जमावडा लगा रहता है. उन्हें

रोकने-टोकने या मना करने पर वे मारा-मारी और गाली-गलौज पर उतारू हो जाते हैं. इससे इस कॉम्प्लेक्स के रहिवासियों में दहशत का माहौल बना रहता है. हाल ही में ड्रग्स एडिक्ट कुछ अपराधी तत्वों द्वारा तलवारबाजी कर इस कॉम्प्लेक्स के २ रहिवासियों को घायल किए जाने की घटना भी घटित हुई है. इसी के मद्देनजर फेडरेशन ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, ताकि दोबारा इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति न हो. फेडरेशन के शिष्टमंडल के निवेदन पर गौर करते हुए नया नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे ने उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और पूनम सागर कॉम्प्लेक्स परिसर में पुलिस गस्त बढाने, सीसीटीवी तथा समुचित लाइट की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है.

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मनपा की कारवाई हुई तेज

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए सख्त कदम उठाया है. टैक्स वसूली में कोताही करने वाले १८ कर्मचारियों को हाल ही में दूसरे विभागों में तबादला कर दिया गया है. वहीं वर्षों से टैक्स न अदा करने और ९८ लाख ९० हजार रुपए बकाया होने के कारण ब्लू मून क्लब को सील कर ताला मार दिया गया है. बता दें कि मनपा के मुख्य आय का स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) है. चालू वित्तीय वर्ष में मनपा को प्रॉपर्टी टैक्स से २३२ करोड. रुपए की आय अपेक्षित है, । जिसमें से करीब १३० करोड.रुपए की वसूली अब तक हो - चुकी है. जिसमें से बकाया १३२ करोड. रुपए वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मार्च २०२४ तक शत- प्रतिशत वसूली का सख्त आदेश आयुक्त संजय काटकर ने टैक्स (कर) विभाग को दिया है. इसके अनुसार कर विभाग ने वसूली टीम तैयार कर टैक्स बकायेदारों के घर, दुकानों पर जाकर पीओएस मशीन की सहायता से टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मनपा ने कर दाता नागरिकों को कर अदा करने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई है. कर विभाग को आगामी ४ माह में शत-प्रतिशत कर वसूली के लक्ष्य को पूरा करना है.

संपादकीय

संपादक सीमा गुप्ता

मुंबई की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

मुंबई पर हुए २६/११ के हमले की १५ वीं बरसी है। हमले के बाद मुंबई और आसपास के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पुलिस को ३० बोट दी थीं। मगर आज हालत यह है कि इनमें से अधिकांश बोट खराब हो चुकी हैं, जिससे मुंबई की सुरक्षा पर फिर खतरा मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल २३ बोटों में से सिर्फ आठ बोटों का इस्तेमाल हो रहा है। १३ बोट बिना मरम्मत के किनारे पड़ी हैं। इसके बावजूद पुलिसकर्मी इन बोटों के माध्यम से सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह नई मुंबई में समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात सात बोटों में खराबी आने के कारण पिछले कई वर्षों से मरम्मत के इंतजार में खड़ी हैं। जबकि वहां किराए के बोट से सुरक्षा का काम किया जा रहा है। बता दें कि मुंबई में हुए २६/११ आतंकी हमले के बाद मुंबई सहित इससे लगे समुद्री किनारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें मुंबई से लेकर कोकण तक की समुद्री किनारों को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि मुंबई से कोकण तक १४४ किमी की समुद्री सीमा लगी हुई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस समुद्री सुरक्षा को रामभरोसे छोड़ दिया गया है। वर्ष २०१८ से ही नई मुंबई की सातों बोट मरम्मत के इंतजार में बेलापुर के पास खड़ी हैं। इसमें से एक बोट पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बाकी की बोट मरम्मत के इंतजार में हैं। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल २३ बोटों को १२ वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और नियमत: उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने इन बोटों की आधुनिक तरीके से मरम्मत कर, इनकी उम्र बढ़ाने पर जोर दिया है। जैसे ही बोट मुंबई-२ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, अब १३ और बोटों को आधुनिक सिस्टम से मजबूत किया जाएगा। फिलहाल, दो बोटों की मरम्मत करने का काम चल रहा है। ऐसे में समुद्री रास्ते की सुरक्षा कैसे करें? यह सवाल पुलिसकर्मियों के सामने है। अब देखना यह है कि कब तक ये बोट बनकर सुरक्षा में तैनात होती हैं। मुंबई पुलिस के नौका विभाग के डीसीपी निंबा पाटील ने बताया कि मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल नाव मुंबई-२ को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इस बोट में नया इंजन लगाया गया है, इसलिए १० से १५ नॉटिकल मील की रफ्तार से चलने वाली इस बोट की क्षमता बढ़ गई है और नए इंजन के कारण यह बोट अब ३० से ३५ नॉटिकल मील की रफ्तार से गश्त कर रही है। इसके अलावा इस बोट के रडार सिस्टम और अन्य पहलुओं को भी अधिक कुशल बनाया गया है और इसके कारण इसकी उम्र सात से आठ साल तक बढ़ गई है। मुंबई पुलिस को दिए गए २३ स्पीड बोट के रख-रखाव के दौरान ठेकेदारों द्वारा १३ स्पीड बोटों के इंजन बदलकर पुराने और कमजोर इंजन लगा दिए गए थे। इसकी जानकारी होने पर मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया। इस मामले में अभी जांच शुरू है। इस बीच मुंबई पुलिस की तरफ से २२ बोटों की खरीदारी के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें १२ का इस्तेमाल समुद्री किनारों की गश्ती के लिए किया जाएगी, इनमें आठ इंटरसेप्टर और दो होवरक्राफ्ट हैं।

आगामी गणतंत्र दिवस पर घोडबंदर किले का लोकार्पण

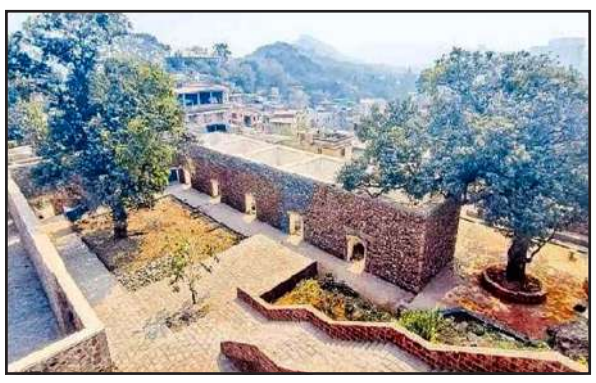

भाईंदर : आगामी गणतंत्र दिवस पर घोडबंदर किले का लोकार्पण किया जाएगा। विधायक प्रताप सरनाईक के साथ एक सयुंक्त निरीक्षण के दौरान मनपा आयुक्त संजय काटकर ने यह आश्वासन दिया। मनपा आयुक्त ने कहा कि २६ जनवरी, २०२४ तक घोडबंदर के ऐतिहासिक किले और अश्वारुद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घोडबंदर किले के लिए निधि का आवंटन किया है। विधायक सरनाईक और मनपा आयुक्त काटकर ने भाईंदर पूर्व में वन रहे स्व. बाला साहेब ठाकरे आर्ट गैलरी, स्व. प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी और नानासाहेब धर्माधिकारी सांस्कृतिक हॉल का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा घोडबंदर खाडी तट, जल परिवहन के लिए मैरी टाइम बोर्ड के माध्यम से फाउंटेन होटल के सामने बन रही प्रवासी जेटी, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर चेना रिवर फ्रंट परियोजना का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान शहर अभियंता दीपक खांवित, उप अभियंता यतिन जाधव और मनपा तथा वन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

निजी ट्रैवल्स की बसों पर वसुला जुर्माना

जेकेएस संवाददाता

मुंबई। दिवाली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त आर्थिक लूट को रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने निजी ट्रैवल्स बसों की जांच के लिए १० से १९ नवंबर तक दहिसर चेक पोस्ट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। १० दिवसीय अभियान के तहत विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों का निरीक्षण किया गया। इसमें दोषी पाई गई ८८ बसों से दो लाख पच्चीस हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। दिवाली के मौके पर आम नागरिकों से लूटपाट रोकने और बिना उचित दस्तावेजों के निजी यात्राओं पर कार्रवाई करने के लिए आरटीओ विभाग ने दहिसर चेक पोस्ट पर एक विशेष चेकिंग टीम नियुक्त की थी। इस टीम में विरार आरटीओ के ४ अधिकारी शामिल थे। विशेष चेकिंग टीम ने दहिसर चेक पोस्ट पर दिवाली के दौरान

निजी ट्रैवल्स की जांच करके ८८ प्राइवेट ट्रैवलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। आरटीओ द्वारा की गई कार्रवाई में यह पता चला है कि अतिरिक्त किराया, पात्रता प्रमाण पत्र की कमी, कर का भुगतान न करना, आपातकालीन द्वार न खोलना, ड्रैजीलिंक लाइट और अमान्य दस्तावेजों के मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में प्रवीण बागडे. (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विरार) ने बताया कि, प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने दिवाली के दौरान निजी बसों के लिए एक निरीक्षण अभियान चलाया था। जिसमे कई बसों की जांच की गई जिसमें से ८८ बसों पर करवाई करके उनसे दो लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

मनपा की तिजोरी खाली के चलते सड़को का कंक्रीटीकरण रुका

जेकेएस संवाददाता

भायंदर। मीरा भायंदर की सड़कों का कंक्रीटीकरण(सीसी) करने के दावे और फैसले हवाई साबित हो रहे हैं।धनाभाव के चलते तकरीबन ३७ सीसी रोड के काम शुरू होने से पहले रोक दिए गए हैं।जबकि ठेकेदारों को कार्यादेश तक दिया जा चुका था। इन कामों के लिए ५०० करोड रुपए की लागत तय की गई है।यह रकम कर्ज से प्राप्त की जानी थी। लेकिन मीरा भायंदर मनपा ने अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए लोन लेना फिलहाल टाल दिया है। और लोन की किस्त का भार सरकार पर डालने की फिराक में है। मीरा भायंदर मनपा के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर ने राज्य के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर कर्ज की किस्त खुद(सरकार) चुकाने की मंजूरी देने की गुहार लगाई है। पत्र के अनुसार सड़कों के कंक्रीटीकरण के पहले चरण में ५०० करोड रुपए का कर्ज बैंक ऑफ बड़ोदा से लेने का निर्णय मीरा भायंदर मनपा ने १७ नवंबर २०२२ को किया था।यही नहीं निविदा प्रक्रिया पूरी कर ठेकदारों को कार्यदेश भी दिया जा चुका है।लेकिन खाली तिजोरी के कारण उन्हें काम शुरू करने से मना कर दिया गया है। आयुक्त ने हवाला देते हुए कहा है मीरा भायंदर की आबादी में इजाफा और शहरीकरण तेजी से हो रहा है।मनपा की संपत्तियों की देखभाल और मरम्मत आदि का खर्च देखते हुए सीसी रोड बनाने के लिए लोन लेना मीरा भायंदर मनपा की क्षमता से बाहर की बात है।लेकिन सीसी सड़क बनाना जरूरी है।इसलिए कर्ज की किस्त चुकाने का जिम्मा राज्य सरकार को खुद अपने ऊपर लेना चाहिए। मीरा भायंदर में ११५० करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड बनाने का निर्णय लिया गया था।इसमें से ५०० करोड़ रुपए एमएमआरडीए से अनुदान,५०० करोड़ कर्ज और १५० करोड.रूपया मनपा की तिजोरी से आने थे।जिसमें से एमएमआरडीएस के खर्च से होने वाले ३८७ करोड रुपए के तथा मनपा के खर्च से होने वाले ५०० करोड रुपए(८८७ करोड.रुपए) के काम के लिए ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए हैं।और उन्हें कार्य आदेश भी दे दिया गया है।इसके अलावा १५७ करोड़ रुपए लागत के अलग–अलग सीसी रोड के निर्माण चालू हैं। वहीं ५५ करोड़ के तीन अलग–अलग सीसी रोड के काम के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं।इस तरह कुल ११५४ करोड़ रुपए की लागत का काम शुरू और शुरू होने वाले थे। लेकिन अब मीरा भायंदर मनपा के खाली खजाने के चलते ५०० करोड़ की लागत के ३७ सीसी रोड के काम अधर में लटक गए हैं।

मीरा–भाईंदर में मेट्रो निर्माण मार्ग पर छाया अंधेरा

जेकेएस संवाददाता

भायंदर । मेट्रो निर्माण मार्ग की स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से अंधेरा छाया रहता है। ऊपर से पर्याप्त रिफ्लेक्टर व रिफ्लेक्टर लाइट न होने से दुर्घटना होती रहती है।एमएमआरडीए तथा मीरा भायंदर महानगरपालिका सब कुछ जानते हुए भी अनदेखी कर रही है। भायंदर – काशीमीरा रोड के मध्य में मेट्रो मार्ग का निर्माण चालू है।मार्ग के दोनों दिशा में अधिकांश स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। जिससे शाम ढलते ही सडक़ पर अंधेरा छा जाता है। मेट्रो मार्ग निर्माण का काम करने वाली कंपनी जे.कुमार कुछ महीने पहले अधिकांश बैरिकेडिंग हटा दिया था।कुछ जंक्शन को छोड.दे तो सडक़ के अधिकांश हिस्से में रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर लाइट ही नहीं है। जिससे दुर्घटना होती रहती हैं।और बडे.हादसे का खतरा बना हुआ है।भाजपा नेता गजेंद्र भंडारी ने कहा कि ऐसा लगता है प्रशासन को नागरिकों की जान की परवाह नहीं है।इस संबंध में हमने मीरा भायंदर मनपा के सिटी इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

मेडिकल खर्च में दर्ज हुई १४ प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुंबई : अब तक जहां एक ओर हिंदुस्थान के आम आदमी को बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी और क्या खाएं, क्या पकाएं की चिंता सता रही थी। वहीं दूसरी ओर बेतहाशा बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी को इलाज कराना भी मुश्किल हो चला है। आलम यह है कि बीते पांच सालों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला खर्च बढ़कर दोगुना हो गया है और हर साल १४ प्रतिशत महंगा हो रहा है। अच्छे डॉक्टरों की महंगी फीस के बाद अब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियों की दवाओं पर भी महंगाई का असर हुआ है। इन दवाओं की सूची में एंटीबायोटिक, एंटी–इंफेक्शन, पेन किलर, दिल की बीमारी की दवाएं सबसे ऊपर हैं। कोरोना महामारी के बाद से अस्पताल में इलाज करना भी महंगा हो चला है। पिछले ५ सालों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला खर्च दोगुना हो गया है। एक तरफ जहां सामान्य महंगाई दर ७ परसेंट के आस पास है वहीं मेडिकल खर्च १४ फीसद की दर यानी दोगुने से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इससे ये बात साफ है कि वैंद्र में बैठी मोदी सरकार के राज में अब इलाज करना भी महंगा हो गया है। दरअसल, एशिया में मेडिकल खर्च की महंगाई दर सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिली है। २०२३ के अनुसार, देश में मेडिकल महंगाई दर १४ फीसदी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुस्थान में मेडिकल इलाज महंगा हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में मेडिकल खर्चों के कारण ९ करोड़ से अधिक हिंदुस्थानियों की जिंदगी पर प्रभाव देखने को मिला है। उनकी कमाई का १० प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल बीमारियों के इलाज में चला जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश में नौकरीपेशा लोगों की आबादी साल २०३० में बढ़कर ५६.९ करोड़ हो जाएगी, जो कि साल २०२२ में सिर्फ ५२.२ करोड़ ही थी। वैंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा को लेकर २० से ३० साल के युवाओं के बीच जागरूकता बहुत कम है।

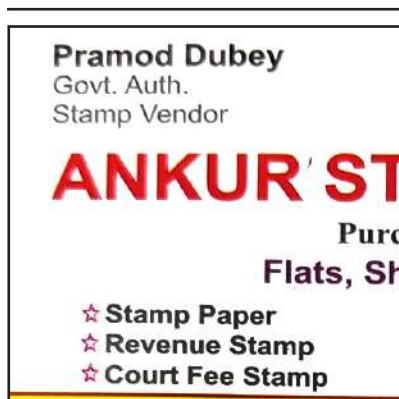

अवकाश के दिन में भी भर सकते है प्रॉपर्टी टैक्स

जेकेएस संवाददाता

भाईंदर : मनपा अपनी कमाई बढाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को बढाने और तेज करने के लिए मनपा लगातार काम कर रही है। इसी कडी में मनपा आयुक्त संजय काटकर ने छुट्टी के दिन भी टैक्स वसूली केंद्र को खुले रखने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त के निर्णय के अनुसार, अब सभी टैक्स कलेक्शन सेंटर सुबह ९.४५ से शाम ६.१५ बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा, शासकीय और अन्य छुट्टी के दिन भी केंद्र सुबह ९.४५ से शाम ४ बजे तक खुले रहेंगे। यह नियम आगामी ३१ मार्च २०२४ तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि मनपा बजट में इस बार २४० करोड.की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य है। आधे से अधिक वित्त वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक मात्र १३२ करोड.की वसूली हुई है। वसूली को बढाने के उद्देश्य से मनपा ने एक बैंक से २३ पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल्स) मशीन ली है। इस मशीन के माध्यम से मनपा कर्मचारी घर–घर जाकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई में माध्यम से भी टैक्स के भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं। टैक्स वसूली में हो रही सुस्ती का आयुक्त ने संज्ञान लिया है। इसी के चलते आयुक्त ने कर विभाग से १८ कर्मचारियों का अन्य विभागों में तबादला कर दिया है।

डीपफेक के बाद अब क्लियरफेक का खतरा!

मुंबई : डिजिटल और इंटरनेट के इस दौर में साइबर अपराधों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। काफी लोग इस सायबर अपराध के शिकार बन रहे हैं। इनमें डीपफेक काफी खतरनाक बनकर उभरा है, जिसकी शिकार मशहूर हस्तियां हो रही हैं। अब केंद्र सरकार भी इसके खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में है। इन सबके बीच साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्लियरफेक के खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, स्वैमर्स किसी व्यक्ति की तरह दिखने वाली तस्वीरें, वीडियो बनाने के लिए एआई के सहारे डीपफेक का उपयोग करते हैं। यह किसी व्यक्ति की तरह लगने वाला ऑडियो भी बना सकता है। इसी तरह, जब साइबर अपराधी किसी वेबसाइट की नकल करते हैं, तो इसे क्लियरफेक कहा जाता है। हैकर्स किसी वेबसाइट की हू-बहू नकल करके वैसी ही दिखने वाली दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं। इस वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को अपना ब्राउजर अपडेट करने के लिए कहा जाता है। चूंकि यह असली वेबसाइट की तरह दिखती है, इसलिए यूजर को पता नहीं चलता कि इसमें कोई धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए यूजर्स अपने ब्राउजर को अपडेट करने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यूजर के पीसी में एक अलग ब्राउजर इंस्टॉल हो जाता है। इसके जरिए कंप्यूटर में एटॉमिक मैकओएस स्टीलर मैलवेयर इंस्टॉल किया जाता है। यह मैलवेयर वास्तव में मैक कंप्यूटरों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस वजह से यह साधारण सुरक्षा दीवारों को भी आसानी से बायपास कर सकता है। यह मैलवेयर कंप्यूटर से सभी संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। इतना ही नहीं, क्लियरफेक का इस्तेमाल लोगों के कंप्यूटर पर अन्य मैलवेयर और वायरस इंस्टॉल करने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने के लिए भी किया जाता है। विशेषज्ञों ने इससे सावधान रहने की चेतावनी दी है। अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करते रहें। नए ऐप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय इसे आधिकारिक स्रोत से प्राप्त करें। कंप्यूटर में एंटी वायरस इंस्टॉल करें।

कहां गईं ४० हजार टिकटें? फाइनल में भी फ्रॉड!

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : हाल ही में संपन्न हुए क्रिकेट वर्ल्डकप में टिकटों के मामले में जमकर फ्रॉड हुआ। अधिकांश क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया द्वारा खेले जानेवाले मैचों के टिकटों की तलाश में मारे-मारे फिरते रहे, पर न तो उन्हें ऑफ लाइन टिकट मिला और न ही ऑन लाइन। पता नहीं ये टिकट कहां बिक रहे थे और कौन खरीद रहा था। मगर हद तो तब हो गई जब अमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भी टिकटों के फ्रॉड का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फाइनल मैच के करीब ४० हजार टिकट लापता हो गए। दरअसल, इसका गणित बहुत सीधा है। अमदाबाद स्टेडियम की क्षमता एक लाख ३२ हजार बताई गई है। फाइनल मैच के दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अब आईसीसी ने कहा है कि फाइनल मैच के दिन स्टेडियम में ९२,५४३ दर्शक आए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर ४०,००० टिकट कहां गायब हो गए? जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरा स्टेडियम १ लाख ३२ हजार दर्शकों से भरा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम खचाखच भर गया था। स्टेडियम में चींटी के घुसने की भी जगह नहीं थी। खाली सीटें न होने के कारण हजारों दर्शक स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। हालांकि, आईसीसी ने घोषणा की है कि स्टेडियम में सिर्फ ९२,५४३ दर्शकों की उपस्थिति थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या वहां फर्जी टिकट तो नहीं बेचे गए थे? या फिर बहुत से लोगों को बिना टिकट के ही स्टेडियम में प्रवेश दे दिया गया था। लोगों का कहना है कि चाहे जो भी हुआ है पर फ्रॉड तो हुआ ही है। आईसीसी ने घोषणा की थी कि इस साल विश्व कप में १२,५०,३०७ दर्शकों ने स्टेडियम में मैच देखा। यह अब तक की सबसे ज्यादा दर्शक संख्या है। इस साल विश्वकप के ४८ मैचों में इतनी भीड़ आई है और हर मैच में औसतन २६ हजार दर्शक पहुंचे। इससे पहले २०१५ में १०,१६,४२० दर्शकों ने मैच देखा था। २०१९ वर्ल्ड कप में ये आंकड़ा ७,५२,००० तक था। इस बारे में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल कहते हैं कि वहां सुरक्षाकर्मियों, स्वयंसेवकों, बुक माई शो के प्रतिनिधियों, लाइव प्रसारण दल और सुरक्षा गार्डों को भी पहचान पत्र दिए गए थे, लेकिन इनमें से किसी को भी कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं थी। हमने २,००० से अधिक मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया था। उनके टिकट स्कैन नहीं हुए। हमारे पास भी एक सिस्टम है। आईसीसी, बीसीसीआई के प्रतिनिधि हैं। कुल मिलाकर मैदान में उपस्थिति करीब सवा लाख के आसपास थी। मैदान में प्रवेश पर प्रत्येक टिकट बारकोड को स्कैन किया गया था। इसी से आईसीसी को मैदान में दर्शकों की मौजूदगी का पता चला। अब सवाल है कि अगर स्टेडियम में १ लाख ३२ हजार से ज्यादा दर्शक थे तो सिर्फ ९२,५४३ दर्शकों के टिकट ही क्यों स्कैन हुए? अब अगर १ लाख ३२ हजार टिकट बिके तो सिर्फ ९२,५४३ टिकट ही क्यों स्कैन हुए? बाकी टिकटों का क्या हुआ? अब यदि ९२,५४३ दर्शक ही मैदान में थे तो बाकी ४० हजार दर्शक मैदान में कैसे आए?

भ्रष्टाचार का अड्डा बना जेएनपीटी कस्टम हाउस! अधिकारियों की मनमानी से इम्पोर्टर हुए परेशान

मुंबई : जहां एक ओर केंद्र सरकार इज ऑफ डूइंग व्यापार का राग अलाप रही तो वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) कस्टम हाउस भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इसका कारण है इम्पोर्टर्स द्वारा विदेश से मंगाए जानेवाले माल पर कानूनी दांव-पेच बताकर लाखों रुपए वसूल किया जा रहा है, नहीं दिए जानेवाले व्यापारियों को कंटेनर सीफेस में फंसे होने के कारण लाखों रुपए का नुकसान सहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसको लेकर बृहन्मुंबई कस्टम ब्रोकर असोसिएसशन की तरफ से स्टील आयात पर अधिकारियों द्वारा होनेवाली समस्या को लेकर जेएनपीटी कस्टम आयुक्त को लेटर लिखकर समस्याओं से अवगत भी कराया था। सूत्रों की मानें तो इम्पोर्टरों के कई कंटेनर दिवाली से पहले से ही कंटेनर प्रेंट स्टेशन (सीएफएस) यार्ड में फंसे हुए हैं, जिससे रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान और देरी का कारण भ्रष्ठ अधिकारियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रावधानों की गलत व्याख्या करना और मंजूरी के लिए भारी रिश्वत की मांग करना है। हालांकि, स्टील लॉबी ने हाल ही में दिल्ली में व्यापार और उद्योग मंत्रालय से स्पष्ठीकरण प्राप्त किया है, जिससे कुछ राहत मिली है। इसके बावजूद हजारों कंटेनर अभी भी अधिकारियों के टेबल पर फाइल धूल खा रहे है और यार्ड के इम्पोर्टर उनके द्वारा की गई देरी के कारण दंड भरने को मजबूर हैं इम्पोर्टर बिना नाम न छापने की शर्त पर बता रहे हैं कि ग्रुप ५ के सहायक आयुक्त जैसे अधिकारियों के कारण सबसे अधिक परेशानी हो रही है। इस अधिकारी द्वारा प्रति शिपमेंट पर लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। सूत्रों का आरोप है कि इस सहायक आयुक्त के लिए सीधे धनउगाही में शामिल हैं। इस अधिकारी पर कस्टम हाउस एजेंटों से खुलेआम धनउगाही करने, धमकी और धमकी के माध्यम से भय पैदा करने, आयात प्रक्रिया में बिचौलियों पर अतिरिक्त बोझ डालने का भी आरोप है। इस साल जुलाई महीने में सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त ने एक ऑनलाइन न्हावा-शेवा शिकायत निवारण पोर्टल ई-समाधान शुरू किया था। हालांकि, पीड़ितों का कहना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से हम सबसे इस तरह के अधिकारियों के निशाने पर आ जाएंगे, जिसके परिणामस्वरुप हम कस्टम अधिकारियों के दुश्मन बन जाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि जेएनपीटी कस्टम हाउस में व्याप्त भ्रष्ठाचार भारत में व्यापार करने में आसानी प्रदान करने के सरकार के उद्देश्यों के विपरीत है। इम्पोर्टर खुद को असहाय और आर्थिक रूप से तनावग्रस्त पाते हैं, जबकि भ्रष्ठ अधिकारी कथित तौर पर अवैध धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे में इन आरोपों की जांच करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है। जेएनपीटी कस्टम हाउस को आयात-निर्यात व्यापार के लिए निष्पक्ष और भ्रष्ठाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल करनी चाहिए।

घर-घर जाकर संपति कर वसूलेंगे मनपा अधिकारी

जेकेएस संवाददाता

भायंदर। संपति कर भरने में अब टालमटोल नहीं चलने वाली है। मीरा भायंदर मनपा के कर वसूली अधिकारी अब सीधे करदाता के घर पहुंचेंगे और कर भरने की डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मंगलवार को कर वसूली अधिकारियों को पीओएस(पॉइंट ऑफ सेल) मशीन से लैस कर दिया गया। उपायुक्त(कर) संजय शिंदे ने बताया कि घर बैठे कर भरने के लिए पहले ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। मीरा भायंदर मनपा की वेबसाइट और मोबाइल एप से कर भरा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ करधारक समय पर कर नहीं भरते हैं। ऐसे कर धारकों को कर भरने की व्यवस्था हम सीधे उनके घर पर उपलब्ध करा रहे हैं।इसके लिए हमने २३ कर वसूली अधिकारी के हाथ पीओएस मशीन थमाया है। इस मशीन में क्यूआर कोड स्कैन कर,डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भरने की सुविधा है।मशीन में भुगतान रसीद देने की भी सुविधा है।करदाता रसीद की द्वितीय प्रति मनपा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। उपायुक्त शिंदे ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में २३२ करोड.रूपया रूपया गृह कर अपेक्षित है। जिसमें से अब तक १३० करोड.रूपया वसूल हो चुका है।बाकी का १३२ करोड.रूपया वसूलने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है।इसके लिए हमने कर वसूली अधिकारियों को घर-घर भेजने का निर्णय लिया है।

हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना: मासूम लड़का सहित ३ की दर्दनाक मौत: ३ घायल

पालघर : मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे खतरनाक मोडों और ब्लैक स्पॉट के कारण दिन-ब-दिन खतरनाक होता जा रहा है। ऐसी खतरनाक स्थितियों के कारण दैनिक दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। गुरुवार, २३ नवंबर को पालघर के मेंढवन घाट पर एक भयानक कार दुर्घटना हुई। इस भीषण हादसे में ३ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे, जिनमें एक ५ साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे में ३ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है और उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जिस मोड.पर यह हादसा हुआ, वहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस हाईवे के निर्माण के बाद से अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। उधर हादसे में शामिल लोग पुणे के थे। मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार २३ नवंबर को मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पालघर के मेंढवन घाट पर भीषण हादसा हो गया। मुंबई से गुजरात जा रही एक हाईस्पीड कार का नियंत्रण खो गया, तो कार मेंढवन घाट के खतरनाक मोड.से विपरीत दिशा में जाने लगी और सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई।हादसा इतना भीषण था कि पूरी कार चकनाचूर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मृतकों की पहचान हर्षद गोडबोले (४२), आनंदी गोडबोले (५) और ड्राइवर मिलिंद वैद (४३) के रूप में हुई है। साथ ही घायलों के नाम हर्षदा गोडबोले (३७), अद्वैत गोडबोले (१२) हैं।

कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल, वो ५ हजार ३३१ आखिर जाता है किसकी जेब में?

मुंबई : राज्य के ग्राम पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन ऑपरेटरों का यह आंदोलन १७ नवंबर से चल रहा है। अभी तक कोई समाधान नहीं है। ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग से पद सृजित कर नियुक्त किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने न्यूनतम वेतन दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आरोप लगाया है कि सीएससीएसपीवी से जबरन वसूली की जा रही है। इस बीच सीएससीएसपीवी कंपनी द्वारा जबरन वसूली वास्तव में कैसी है? इसकी जानकारी खुद कंप्यूटर ऑपरेटर ने दी है। कंप्यूटर ऑपरेटर का निर्धारित वेतन ७ हजार रुपए है, लेकिन हकीकत में वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायत को १२ हजार १,३३१ रुपए भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत इस फंड को सीएससीएसपीवी नामक कंपनी को भेजती है। कंपनी इस फंड से कंप्यूटर ऑपरेटरों को केवल ७ हजार रुपए का भुगतान करती है। महाराष्ट्र स्टेट कंप्यूटर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे ने बताया कि सीएससीएसपीवी स्टेशनरी के नाम पर बाकी ५ हजार ३३१ रुपए काट रहा है। दरअसल, ग्राम पंचायत के लिए प्रति माह एक रीम कागज, एक टोनर की आवश्यकता होती है। यह लागत सीएससीएसपीवी द्वारा वहन नहीं की जाती है। सिद्धेश्वर मुंडे ने कहा कि स्टेशनरी का भुगतान ग्राम पंचायत कर रही है तो फिर सीएससीएसपीवी द्वारा ५ हजार ३३१ रुपए काटने का क्या कारण है? मुंडे ने कहा कि पैसे का भुगतान कंप्यूटर ऑपरेटर को करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के २७ हजार कंप्यूटर ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे ग्राम पंचायत के प्रशासन पर बड़ा असर पड़ता दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम पंचायत ठप हो गई है। वहीं ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर को अलग से स्वतंत्र पद निर्माण कर नियुक्त किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने न्यूनतम वेतन दिए जाने की भी मांग की है। पिछले १२ वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत स्तर पर सौंपे गए कार्य कर रहे हैं। प्रशासकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के करीब सात करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार काम कर रहे हैं।

काले जादू के नाम पर महिला से ७८ लाख की ठगी

नई मुंबई : नई मुंबई के वाशी में एक व्यक्ति ने करीब ५ लोगों पर उसकी पत्नी को काले जादू का डर दिखाकर ठगने का मामला दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी पत्नी को बताया कि उसके घर पर बहुत खराब होने वाला है, ऐसे में अगर वह उस बाबा से पूजा करवाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। उनकी बातों में आकर पीडित महिला ने पूजा करवाया तो आरोपियों ने उससे घर का सारा सोना वहां लाकर रखने को कहा। महिला ने जब सब सोना रखा तो वो लोग उसे लेकर चले गए और उसके बाद महिला को धमकी दे-देकर कई बार उसे करीब ३६ लाख रुपए ठग लिए। जब महिला की बेटी और दामाद ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अगर वो लोग चुप नहीं रहे तो दोनों को मार दिया जाएगा। इससे पीडित महिला घबरा गई और इसी घबराहट के चलते उसे पैरालिसिस हो गया और वह अब भी खाट पर पडी है। उसके पति ने वाशी पुलिस स्टेशन में सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वसई विरार मनपा कर रही है विभिन्न उपाय

जेकेएस संवाददाता

वसई। वसई-विरार शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महानगर पालिका द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसमें महानगर पालिका द्वारा इन दिनों शहर की सडक़ों पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए मुख्य सडक़ों पर ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। कुल पांच बडी और मुख्य सडक़ों पर काम चल रहा है और महा नगरपालिका के अधिकारी ने बताया कि ९० फीसदी काम पूरा हो चुका है। मुंबई और वसई विरार में भी वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का अनुभव हुआ है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मनपा ने पहले से ही शहर में कई उपाय किए हैं, मियावाकी पार्क बनाए हैं और विभिन्न स्थानों पर फव्वारे लगाए गए हैं। अन्य उपाय भी किये गये हैं,इनमें से एक है सडक़ किनारे ब्लैक टॉपिंग।मुख्य एवं यातायात सडक़ों पर लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के कण हवा में मिल जाते हैं।इससे वायु प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए महानगर पालिका ने ब्लैक टॉपिंग कराई जा रही है । यह कार्य शहर की पांच प्रमुख सडक़ों पर किया गया है। १८ हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। मनपा के उपायुक्त किशोर गवस ने बताया कि इसके लिए ४ करोड.९६ लाख रुपये खर्च करेगी। यह ब्लैक टॉपिंग छह मुख्य सडक़ों पर की जाएगी। ब्लैक टॉपिंग का मतलब है सडक़ के किनारे पहले पक्कीकरण और उसके बाद डामरीकरण किया जा रहा है। फिलहाल महानगर पालिका द्वारा ब्लैक टॉपिंग का ९० प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा,वसई विरार शहर महानगरपालिका उपायुक्त किशोर गवस ने कहा है।

सब पुलिस निरीक्षक तेजश्री शिंदे को बाल स्नेही पुरस्कार से सम्मानित

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ द्वारा पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण सभागार, मुंबई में आयोजित किया गया। जहा पर भायंदर पुलिस स्टेशन में कार्यरत भरोसा सेल की सब इंस्पेक्टर तेजश्री शिंदे को बाल स्नेही पुरुस्कार से सम्मानित किया गया ! यह सम्मान महिला व बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुशीबेन शाह, महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे, तथा विशेष पुलिस महानिरीक्षक दीपक पांडे की उपस्थिति में दिया गया! मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत कार्यरत पुलिस निरीक्षक, तेजश्री शिंदे ने बच्चों के यौन शोषण और अन्य अपराधों के बारे में बच्चों में जागरूकता पैदा करने स्कूली छात्रों और निवासियों के लिए 'कानून पाठ' गतिविधि का आयोजन कर ७५ कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग ४० स्कूलों और २५ हजार छात्रों में जन । जागरूकता पैदा की गई है। साथ ही १ अक्टूबर २०२३ को भरोसा सेल का दूसरा वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। १३ अक्टूबर को पुलिस आयुक्त मीरा भायंदर वसई विरार ने सहायक पुलिस निरीक्षक तेजश्री शिंदे को २ वर्षों तक उक्त कार्य क्रम में उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी भी किया था ! भरोसा सेल मीरा भायंदर वसई विरार की सहायक पुलिस निरीक्षक तेजश्री शिंदे को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य के लिए पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। जिसको लेकर अनेक लोगो ने उन्हें बधाई दी है।

दहिसर-वर्सोवा कोस्टर रोड, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से जुड़ेगा

मुंबई:- पश्चिम मुंबई के नॉर्थ वर्सोवा से उत्तर मुंबई के दहिसर तक बनने वाले कोस्टल रोड के काम को गति देने के लिए बीएमसी लगातार प्रयासरत है। प्रॉजेक्ट के लिए पिछले दिनों बीएमसी ने कंसल्टेंट की नियुक्ति की थी। अब बीएमसी ने प्रॉजेक्ट के पैकेज बी के तहत बांगुर नगर से माइंड स्पेस मालाड तक बनने वाले कोस्टल रोड के हिस्से के लिए टेंडर जारी किया है। यह हिस्सा गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को भी कनेक्ट करेगा, जिससे पश्चिम उपनगर से पूर्व उपनगर में सीधे पहुंचा जा सकेगा। बीएमसी ब्रिज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि कोस्टल रोड के इस हिस्से को छह हिस्सों में बनाया जाएगा। दूसरे हिस्से के तहत बांगुर नगर से माइंड स्पेस मालाड के भाग का निर्माण किया जाएगा। इस हिस्से के निर्माण के लिए बीएमसी ने शनिवार को टेंडर जारी किया। इच्छुक कंपनियां १ दिसंबर २०२३ तक टेंडर भर सकती हैं। १८ दिसंबर २०२३ को टेंडर ओपन किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत १६,६२१ करोड.रुपये है। वर्सोवा से दहिसर तक मार्ग ६ भागों में विभाजित किया जाएगा। वर्सोवा से बांगुर नगर, बांगुर नगर से माइंड स्पेस मालाड, माइंड स्पेस मालाड से चारकोप नॉर्थ टनल, चारकोप से माइंड स्पेस साउथ पैरेलल टनल, चारकोप से गोराई, गोराई से दहिसर के बीच होगी।

मुंबई के अंधेरी में मुक्ति फाउंडेशन में दादा साहब फाल्के एनजीओ के द्वारा आयोजित अवार्ड शो में शास्त्री सुरेश गुरु ओझा जी को मिला चौथी बार बेस्ट एस्ट्रोलॉजर २०२३ का अवार्ड दादा साहब फाल्के एनजीओ के फाउंडर चेयरमैन कल्याण जी जाना जी के एवं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मुंबई रेहना जी शेख के हाथों किए गए सम्मानित शास्त्री जी ने अपने शुभचिंतकों का किये धन्यवाद

पत पेढ़ी से जुड़े मनपा कर्मचारी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीर

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : मीरा भायंदर महानगरपालिका के कर्मचारियों के २८ वर्ष पुरानी पत पेढ़ी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाल ही में इस पत पेढ़ी के कार्यकारी संचालक गोविंद परब की अकस्मात हृदयाघात से मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ मनपा के आयुक्त –प्रशासक ने मनपा मुख्यालय के प्रांगण में स्थित इस पत पेढ़ी के कार्यालय को मुख्यालय प्रांगण से हटाने की नोटिस दे दी है । इतना ही नहीं तो विधायक प्रताप सरनाईक ने भी पत पेढ़ी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सहकारी संस्था के उपनिबंधक किशन रत्नाले से इस पत पेढ़ी पर प्रशासक की नियुक्ति की मांग कर दी है। जिससे इस पत पेढ़ी से जुड़े मनपा कर्मचारी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। मीरा भायंदर महानगरपालिका के अस्तित्व में आने से पूर्व नगरपरिषद के कार्यकाल में वर्ष १९९४ –९५ में इस पत पेढ़ी की स्थापना तत्कालीन नगरसेवक प्रकाश दूबोले ने की थी। जिसका उद्देश्य पालिका कर्मचारियों को अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों व परेशानियों में मदद करना था। उस समय नगर परिषद के १५० कर्मचारियों को तत्कालीन गणेश नाईक प्रणीत श्रमिक कामगार सेना के बैनर तले लाकर प्रकाश दूबोले ने पत पेढ़ी के कामकाज की शुरुआत की थी। गणेश नाईक जाने के बाद शरद राव प्रणीत म्युनिसिपल कामगार संगठन की यूनियन इस पत पेढ़ी पर रही। इसके बाद भारतीय कामगार सेना के माध्यम से पत पेढ़ी संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस पत पेढ़ी से ८५० कर्मचारी जुड़े हैं और इसका वार्षिक टर्न ओवर करीब १९ करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। विगत ३७ वर्षों में इस पत पेढ़ी ने इससे जुड़े सदस्य (मनपा कर्मचारियों) का विश्वास हासिल करने में सफलता पाई है। इस पत पेढ़ी से दिए जाने वाले कर्ज की किश्त सीधे संबंधित कर्मचारियों के वेतन से जमा हो जाती है, इसलिए आपात परिस्थितियों में कर्मचारियों को बिना किसी कागजी लिखा पढ़ी का झंझट किए यहां से आसानी से कर्ज की प्राप्ति हो जाती है। विगत २८ वर्षों में इस पत पेढ़ी का वार्षिक टर्न ओवर १९ करोड़ रुपए हो जाने के बाद इस पर स्थानीय राजनीतिकों की वक्रदृष्टि पड़नी शुरू हो गई। सर्वप्रथम इस पत पेढ़ी पर कब्जा करने के लिए वर्ष २०१६ में तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता प्रणीत श्रमिक जनरल कामगार संगठन ने इसका प्रयास किया। १६ अक्टूबर २०१६ को संपन्न हुए पत पेढ़ी संचालक मंडल के चुनाव में मनपा के तत्कालीन सत्ताधारियों ने अपना सहकार पैनल के अंतर्गत अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जिसे शिवसेना, श्रमजीवी संगठन, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। मेहता प्रणीत श्रमिक कामगार संगठन ने परिवर्तन पैनल के अंतर्गत अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल १९ सदस्यों के पैनल के लिए हुए चुनाव में सहकार पैनल के १४ और परिवर्तन पैनल को ५ सदस्य विजयी हुए थे। इसके बाद विधायक प्रताप सरनाईक ने भी वर्ष भर पूर्व ३० नवंबर २०२२ को इस पत पेढ़ी के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हुए सहकारी संस्था के उप निबंधक से प्रशासक नियुक्ति की मांग की। जिससे इस पत पेढ़ी पर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पत पेढ़ी से जुड़े एक पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बताया की पत पेढ़ी के वार्षिक टर्न ओवर पर स्थानीय राजनीतिकों की नजर है। इस पर वे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। पत पेढ़ी का कामकाज पारदर्शी है। पत पेढ़ी का ए प्लस ऑडिट किया जाता है। विधायक सरनाईक ने प्रशासक नियुक्ति की मांग भले ही की हो, लेकिन उपनिबंधक पहले पत पेढ़ी के कामकाज की जांच करेंगे, अभी कोई प्रशासक नहीं नियुक्त की गई है।

तमाम विकासकार्यों का सरनाईक ने किया तुफानी दौरा

जेकेएस संवाददाता

भायंदर। ओला मजीवाड़ा के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को मीरा भायंदर में चल रहे तमाम विकास कार्यों का आवश्यक निरीक्षण करने के लिए तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घोड़बंदर से लेकर मीरा रोड, भायंदर आदि क्षेत्र में जाकर चल रहे तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए मनपा अधिकारियों से उनकी समीक्षा करके शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सरनाईक ने भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट स्थित स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे कला दालान का निरीक्षण किया। उनके

साथ मीरा भायंदर महानगरपालिका के आयुक्त संजय काटकर एव शहर अभियांता दीपक खाम्बीत समेत कई पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। यहां मीडिया से बात करते हुए प्रताप सरनाईक ने कहा कि जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मीरा भायंदर क्षेत्र के लिए किसी भी तरह के फंड की कोई कमी नहीं रखी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने १८०० करोड रुपए शहर के रास्तों के निर्माण के लिए दिए हैं तथा १२०० करोड रुपए अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए उनके द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से ६० करोड रुपए की लागत से यह कला दलान बनाया जा रहा है, जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की यादों को सदैव ताजा रखेगा। इसके साथ ही प्रमोद महाजन कला दालान, घोडबंदर किला, घोड़बंदर स्थित शिव सृष्टि एवं जल परिवहन सेवा आदि के लिए भी किसी भी तरह के फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरनाईक ने बताया कि आज इस दौरे पर पालिका के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही तमाम ठेकेदारों को भी बुलाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे कला दालान की इमारत इतनी बडी है कि शायद ही महाराष्ट्र में इस तरह की कोई इमारत दूसरी होगी। इसलिए इस इस प्रतिष्ठा परक धरोहर को बड़ी ही भव्यता के साथ बनाया जा रहा है।

शहर में पानी किल्लत होगी दूर,एमएलडी पानी की चल रही है टेस्टींग

भाईंदर : मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने सूयां जलापूर्ति परियोजना के तहत वसई-विरार महानगर पालिका क्षेत्र में टेस्टिंग पूरी कर ली है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मनपा अपनी तरफ से टेस्टिंग कर रही है। वहीं, मीरा-भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वालों को अभी करीब छह महीने और पानी की किल्लत का सामना करना पड.सकता है। इसकी मुख्य वजह मीरा- भाईंदर को अतिरिक्त पानी की सप्लाई के लिए तैयार हो रहे सूर्या परियोजना के दूसरे फेज का काम ८६ फीसदी हो चुका है। एमएमआरडीए के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार, प्रॉजेक्ट का बचा हुआ काम २०२४ के अप्रैल या मई तक पूरा कर लिया जाएगा। उपनगर की पानी की समस्या हल करने के लिए सरकार ने २०१७ के करीब सूयां जलापूर्ति परियोजना का

काम शुरू करवाया था, लेकिन तकनीकी समेत अन्य वजह से प्रॉजेक्ट का काम तय समय में पूरा नहीं हो पाया है। वहीं, कुछ दिन पहले एमएमआरडीए ने वसई-विरार परिसर में पानी की आपूर्ति के लिए टेस्टिंग खत्म कर दी है। इस परियोजना के तहत, वसई विरार को रोजाना १८५ एमएलडी पानी की सप्लाई होगी। परियोजना के दूसरे फेज के तहत मीरा-भाईंदर परिसर में रोजाना २१८ एमएलडी पानी की सप्लाई होगी। दूसरे फेज के लिए एमएमआरडीए ने टनल तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। परियोजना पूरी होने से उपनगर में रोजाना ४०३ एमएलडी पानी की सप्लाई होगी। सूर्या नदी के पानी को उपनगर तक लाने के लिए ८०.७१ किमी लंबी पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर सरकार १,३२९ करोड.रुपये खर्च कर रही है। बीते कुछ समय में उपनगर का तेजी से विकास कास हुआ है। यहां बडी संख्या में लोग बसने लगे। आबादी में बढोतरी होने के साथ ही स्थानीय लोगों की पानी की समस्या भी बढने लगी। सूयां नदी का पानी यहां पहुंचने से लोगों की पानी की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

सूयां डैम से वसई विरार को मिलने वाला अतिरिक्त १८५ एमएलडी पानी की टेस्टिंग चल रही है। अब मनपा की तरफ से टेस्टिंग की जा रही है। कुछ जगहों पर पानी का प्रेशर बढने से पानी की दिक्कत कम हुई है। जलापूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेद्र ठाकरे ने बताया कि फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। सोमवार को पता चलेगा कि टेस्टिंग जारी रहेगी या बंद होगी। फिलहाल, आधिकारिक तौर पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। इस पर बीजेपी नेता मनोज बारोट ने कहा कि कई राजनीतिक दल पानी सप्लाई का श्रेय लेने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी पानी की टेस्टिंग चल रही है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक-मुद्रक सीमा गुप्ता के लिए (प्रिंटींग) सागर प्रिंट एंड प्रोसेस, प्रगती इंडस्ट्रीयल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००११ से मुद्रित १०१, १ला माला सेक्टर ११ सी-२८, टी.एम.टी. बस स्टॉप के पीछे, शांतिनगर, मीरारोड (पूर्व), जिला थाना ४०११०७ (महाराष्ट्र) से प्रकाशित संपादक - सीमा गुप्ता, सलाहकार : सुधाकर डी., पी.आर.बी अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चन के लिए उत्तरदायी है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र केवल जिला थाना रहेगा।
RNI NO. MAHHIN/2004/17839 Mob.No.9757262120 Email :newsjankalyanseva@gmail.com Jankalyan Seva GST No. 27AGUPG9011BIZI